## राजस्थान सरकार

## स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी—3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी—स्कीम, जयपुर। टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ईमेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 17/ 18928 - 19209

दिनांक :-31/3/2017

महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त, राजस्थान।

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी नगर निगम / परिषद / पालिका, समस्त, राजस्थान।

विषय :- खुले में शौच मुक्त (ODF) हेतु Protocol के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ :- भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 09.03.2017

जैसा कि आपको विदित है, आपके शहर को शौचालयों का निर्माण करवाकर खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया जाना है। खुले में शौचमुक्त घोषित किये जाने हेतु Protocol आपको पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। पूर्व में प्रसारित निर्देशों की निरन्तरता में शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मिलित शर्ते वर्ष 2011 के बाद किसी भी योजना में निर्मित IHHTs का विवरण स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर अपलोड किये जाने व सामुदायिक शौवालयों एवं सार्वजनिक शौचालयों की फोटोग्राफ जो कि चालू हालत में है, को स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने के लिये विभागीय पत्र दिनाकं 21.03.2017 द्वारा आपको निर्देशित किया जा चुका है।

वार्डी / शहरों को खुले में शौचमुक्त किये जाने हेतु अस्वच्छकारी शौचालयों को स्वच्छकारी शौचालयों में परिवर्तित करने का कार्य एक निरन्तर प्रकिया है तथा इस कार्य के चलते भी वार्डी / शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा सकता है, बशर्ते उस वार्ड / शहर में दिन में किसी भी समय कोई व्यक्ति खुले में शौच करता ना पाया जावें।

शहरो / वार्डी को खुले में शौचमुक्त घोषित किये जाने से पूर्व निम्न शर्ती को पूर्ण किया जाना आवश्यक है :--

1. जिन घरों में घरेलू शौचालय (IHHL) बनाने की जगह हो उनमें घरेलू शौचालयों का निर्माण करवाया जावे।

2. जिन घरों में घरेलू शौचालये (IHHL) बनाने की जगह उपलब्ध नहीं है उन घरों हेतु सामुदायिक शौचालयों का निर्माण इस तरह करवाया जावें कि 500 मीटर दूरी के भीतर सामुदायिक शौचालय आसानी से उपलब्ध हों सके।

3. सभी वाणिज्य क्षेत्र (Commercial area) में सार्वजनिक शौचालयों का निमार्ण इस तरह करवाया जावे कि 1 किमी की दूरी के भीतर आसानी से उपलब्ध हो सके।

4. घरेलू शौचालय जो कि वर्ष 2011 के बाद बनाये गये है, कि सूचना आवश्यक रूप से SBM पोर्टल पर अपलोड की जावे।

5. सामुदायिक शौचालयों एवं सार्वजनिक शौचालयों के फोटोग्राफ जो कि चालू हालत में हो को SBM पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जावे। उक्तानुसार ODF Protocol की पालना सुनिश्चित करते हुये आप अपने शहरों को अतिशीघ्र ODF घोषित कर सूचना निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

अतः आप व्यक्तिगत रूचि लेकर अपने शहर को ODF घोषित करने का श्रम करें।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :-3|3|20|7

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 17/ 19 210 -296 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।

2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली — 110011

3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।

4. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।

5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, समस्त राजस्थान।

6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम/ परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।

7. CMAR, निदेशालय।

8. टीमलीडर, PMU स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।

9. प्रोगामर, निदेशालय विभागीय वेवसाइट पर अपलोड हेतु

10. सुरक्षित पत्रावली।

स्ति काला भारतेन्द्र माथुरो स्पुर्ख्य अभियता

## PRAVEEN PRAKASH, IAS Joint Secretary & Mission Director (SBM) GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT



प्रवीण प्रकाश, आई.ए.एस. सयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एस.बी.एस.) भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय



Date: 9th March, 2017

D.O. SBM/AS-35/2017

Sh. Kala Instruct

Sub: CI

Circulate Sub: CI

Circulate Dear

Sub: Clarification on achieving 'Open Defecation Free' (ODF) status

As you are aware, Ministry of Urban Development is implementing Swachh Bharat Mission (SBM) Urban with a goal to make the country clean and open defecation free(ODF) by 2<sup>nd</sup> October 2019.

In the pursuit to make India ODF by 2nd October 2019, Gujarat and Andhra Pradesh have already achieved ODF status and working towards sustaining the same.

- 2. It is indeed heartening to see the enthusiasm with which cities are now stepping up their efforts to declare themselves ODF and also get themselves certified as ODF thorough third party. We hope that in the coming months, more cities will be joining the fray in the face to become ODF and sustain their ODF status.
- 3. While cities are driving different initiatives to become ODF, it may be noted that conversion of insanitary latrine to sanitary latrine is an on-going process and will not come in the way of achieving ODF status.
- A city / ward can be notified/declared as ODF city/ ODF ward if, at any point of 4. the day, not a single person is found defecating in the open.
- 5. The ODF protocol already shared with the cities is going to be strengthened further to increase its credibility and transparency. The revised necessary infrastructure and regulatory conditions to be achieved before declaring a city/ward as Open Defecation Free are as follows:

- i) All households that have space to construct toilet, have constructed one
- ii) All occupants of those households that do not have space to construct toilet have access to a community toilet within a distance of 500 meters
- iii) All commercial areas have public toilets within a distance of 1 kilometer
- iv) Details of all Individual households toilets (IHHL) constructed from 2011 onwards will have to mandatorily be uploaded on the SBM-Urban portal.
- v) Pictures of all functional community and public toilets in the city, irrespective of the date of construction, will have to mandatorily be uploaded on the SBM-Urban portal.

This amendment will come into force with immediate effect, with intimation to the third party inspection agency too.

We wish you all the best in your accelerated journey towards ODF status.

With sincere regards

Yours sincerely.

(Praveen Prakash)

To:

Dr.Manjeet Singh, IAS Principal Secretary – Local Self Government, Rajasthan

## Copy to:

- 1. State Mission Director SBM (U)
- 2. Additional Mission Director (SBM)
- 3. CPHEEO
- 4. Section